माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ 5 लाख रुपये तक की कवरेज वाले गैर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को हटाया जाना चाहिए और लाख रुपए से अधिक के स्वास्थ्य कवर पर प्रीमियम के मौजूदा 18 प्रतिशत के मुकाबले 5 प्रतिशत जीएसटी किया जाना चाहिए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी यह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अफॉर्डेबल बन सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Neeraj Dangi: Shri Haris Beeran (Kerala), Smt. Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri G.C. Chandrashekhar (Karnataka), Shrimati Rajani Ashokrao Patil (Maharashtra), Smt. Phulo Devi Netam, (Chhattisgarh), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Ms. Sushmita Dev (West Bengal) and Smt. Ranjeet Ranjan (Chhattisgarh). Now, Shrimati Jebi Mather Hisham; 'Need to promote Indian art, literature and cinema in order to nurture creative expressions'. Mr. A.A. Rahim and Dr. John Brittas are associating.

Need to promote Indian art, literature and cinema in order to nurture creative expressions

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, as I rise to talk about the need to promote Indian art, literature and cinema in order to nurture creative expressions, I wish to draw the attention of this House to a 2019 Malayalam movie, Lucifer, a political thriller, which was a blockbuster hit. As a sequel to Lucifer, Empuraan was released. Empuraan is an epic Malayalam cinematic creation in terms of its impeccable standard in its making powerful message. ..*(Interruptions)*.. It carries the spine and the courage the maker himself shows. ..*(Interruptions)*.. *

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Both Lucifer and Empuraan stars the legendary actor, Mohanlal, Manju Warrier, Prithviraj; a fearless Director, Murali Gopy, a born script writer. They all stand as beacons of resilience. *..(Interruptions)..* Empuraan has captivated audience with every frame. It is, undoubtedly, a super hit movie on day one itself. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jebi Mather Hisham ji, you have given notice for some other subject. You are talking... *..(Interruptions)..* No, no, आप जो भी बोल रही हैं, it will not go on record now. ..(*Interruptions*)..

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it will not go on record. *..(Interruptions)..* आपने नोटिस कुछ और दिया है और किसी और विषय पर बोल रही हैं। ...(व्यवधान)...आपने सब्जेक्ट कुछ और दिया है और बोल कुछ और रही हैं। It will not go on record. *..(Interruptions)..* The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Smt. Jebi Mather Hisham: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri P. P. Suneer (Kerala), Smt. Phulo Devi Netam, (Chhattisgarh), Shri Haris Beeran (Kerala) and Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra). Ms. Swati Maliwal. 'Concern over unregulated growth of e-rickshaws in Indian cities'...(*Interruptions*).. Maliwal ji, please speak. ..(*Interruptions*).. Maliwal ji, only what you speak will go on record. ..(*Interruptions*).. Please, please. Maliwal ji is speaking. You take your seat. ..(*Interruptions*)..

Ms. SWATI MALIWAL: Thank you, Sir. सर, पहले... ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats.

Ms. SWATI MALIWAL: Sir, please restart my time.

---

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will start now. You please speak.

Unregulated growth of e-Rickshaws in Indian cities

सुश्री स्वाति मालिवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर पहले ई-रिक्शा एक किफायती और इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज बिना निगरानी के चलते ये ज्यादातर दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं। सर, जहाँ और ऑटोज़ और टैक्सीज़ को लेकर बहुत सख्त नियम हैं, वहीं ई-रिक्शा धड़ल्ले से, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी जवाबदेही के चले जा रहे हैं। सर, आप दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन के बाहर देख लीजिए, दिल्ली के किसी भी मार्केट के बाहर देख लीजिए, सैंकड़ों की संख्या में ई-रिक्शा सड़कों के ऊपर खड़े होकर जाम लगाते हुए दिखेंगे। सर, हम यहां यह नहीं कह रहे हैं कि सारे ई-रिक्शा चालक गलत हैं, पर सच यह है कि बहुत अधिक ओवरलोडिंग होती है। एक-एक ई-रिक्शा में, जहां तीन से चार लोग बैठ सकते हैं, वहीं 8 से 10 लोग बिठा दिए जाते हैं।

सर, इन ई-रिक्शा के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि यदि थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ जाए, तो पूरा रिक्शा पलट जाता है। यह भी देखने में आता है कि बहुत सारे ई-रिक्शा चालकों के पास न तो कोई लाइसेंस होता है और न ही किसी प्रकार की ट्रेनिंग। वे रॉन्ग साइड पर चलते हैं, ओवरस्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट तोड़ते हैं - यह सब आम होता जा रहा है।

सर, राज्य सरकारों के पास इनके कोई सटीक आंकड़े भी नहीं हैं। दिल्ली में ही बताया जाता है कि करीब ढाई लाख से ज्यादा ई-रिक्शा सड़कों पर चल रहे हैं, पर कितनों के पास रजिस्ट्रेशन है, कितनों के पास लाइसेंस है - यह किसी को नहीं पता।

सर, एक महीने पहले दिल्ली में एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई, क्योंकि एक तेज़ रफ्तार ई-रिक्शा उससे टकरा गया। कुछ समय पहले दिल्ली में ही एक 7 साल के बच्चे की भी मौत हुई, क्योंकि उसे एक ई-रिक्शा के अवैध चार्जिंग पॉइंट से करंट लग गया। इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

राज्य सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले ई-रिक्शा की संख्या को सीमित करें। ई-रिक्शा और उनके चालकों की लाइसेंसिंग अनिवार्य होनी चाहिए। रूट और स्टैंड निर्धारित होने चाहिए। जितने भी अवैध चार्जिंग पॉइंट्स चल रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए।

सबसे जरूरी बात यह है कि यदि कोई नियम तोड़े, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इस मुद्दे पर राज्य सरकारों की जवाबदेही तय करे।

महोदय, हमें सुविधा चाहिए, लेकिन सिस्टम के साथ। हमें रफ्तार चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और सबसे बड़ी बात, हमें प्रगति चाहिए, लेकिन किसी की जिंदगी की कीमत पर नहीं।

जय हिंद!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Ms. Swati Maliwal: Shri Haris Beeran